concept of integration between agriculture and industry. The integrated approach incorporates economic, technological and organisational aspects and includes all elements of the agricultural production, industrial processing, marketing and distribution process.

4. Cooperation among developing countries in the field of agro-based industries would allow for coordinated development of various stages of production, processing and marketing. Such cooperation will enhance the developing countries' awareness of each others' potential in the field of mutual interest and establish a firm basis for increasing their self-reliance.

राज्य कृषि फार्म

4435. **श्री कुम्भा राम आर्य :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने राज्य कृषि फार्म हैं और प्रत्येक राज्य में वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) इन फार्मों के लिए निगम की स्थापना कब की गई थी और इस निगम ने तारीख वार कौन से कार्यों को अपने हाथ में लिया है;

(ग) इन कृषि फार्मों से कितनी आय हुई तथा इन पर कितना व्यय किया गया है;

(घ) क्या कोई कृषि फार्म घाटे में चल रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर वी स्वामीनाथन): (क) और (ख) भारतीय राज्य फार्म निगम सारे देश में 12 केन्द्रीय राज्य फार्मों की व्यवस्था करता है। राज्य-वार उनके स्थान तथा उनकी स्थापना के वर्ष संलग्न विवरण 1 में किये गए हैं। कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत निगम 14 मई 1969 को निगमित किया गया था। यह निगम मुख्य रूप से अपने आरम्भ से ही धान्यों, दलहनों तिलहनों, रेशे वाली फसलों, सब्जियों आदि के अच्छे किस्म के बीजों का उत्पादन करता है। कन्नानोर में अरालम स्थित फार्म मुख्य रूप से एक बागान फार्म है तथा यह फार्म, नारियल, काजू रबड़, काली मिर्च आदि जैसी अनेक फसलों के लिए अच्छी रोपण सामग्री का उत्पादन करता है। इसके अतिरिक्त मिजोरम में स्थित दो छोटे फार्म सरकार की ओर से विस्तार सम्बन्धी कार्यकलाप करते हैं। निगम उत्तर भूमि सुधार परियोजना के रूप में रायबरेली में एक छोटा फार्म भी चलाता है। इसके अतिरिक्त, निगम अपनी मशीनरी बेड़े का उपयोग करके कस्टम भूमि विकास सम्बन्धी कार्य भी करता है।

(ग) 1980-81 के दौरान विभिन्न फार्मों से हुई आय तथा उनपर हुए व्यय का ब्योरा संलग्न विवरण 2 में दिया गया है।

(घ) 1980-81 के दौरान, पंजाब में लादोवाल, कर्नाटक में रायचूर, असम में कोकिलाबाड़ी, उत्तर प्रदेश में बहराइच तथा रायबरेली तथा तमिलनाडु में चेंगम स्थित फार्मों में हानि हुई है।

(ङ) भारतीय राज्य फार्म निगम के कब्जे में कुल 36671 हैक्टयर क्षेत्र है, जिसमें से 27115 हैक्टयर क्षेत्र को खेती योग्य समझा जाता है। इसकी तुलना में अब तक केवल 17070 हैक्टयर क्षेत्र का उचित रूप से विकास किया गया है। शेष कृषि योग्य क्षेत्र का अभी और विकास करने की आवश्यकता है। लगभग 60 प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई की सुविधायें नहीं हैं। इस प्रकार प्रकृति की अनियमितताओं के कारण फार्मों को हानि होती है।

विवरण-1

भारतीय राज्य फार्म निगम द्वारा चलाये जा रहे फार्मों के स्थान तथा उनकी स्थापना के वर्ष सहित उनकी सूची ।

क्रम संख्या	स्थान सहित फार्म का नाम	स्थापना का वर्ष
1	2	3
1	केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)	1956
2	केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़, जिला श्री गंगानगर (राजस्थान)	1956
3	केन्द्रीय राज्य फार्म जेतसर, जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)	1964
4	केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार (हरियाणा) . . .	1968
5	केन्द्रीय राज्य फार्म, जावलगेरा, जिला रायचूर (कर्नाटक)	1969
6	केन्द्रीय राज्य फार्म, अरालम, जिला कन्नानौर (केरल)	1971
7	केन्द्रीय राज्य फार्म, चेंगम, मेलचेंगम, जिला नार्थ अर्कोट, (तमिलनाडु)	1971
8	केन्द्रीय राज्य फार्म, कोकिलावाड़ी, जिला कामरूप (असम)	1971
9	केन्द्रीय राज्य फार्म, लाढ़वाल, जिला लुधियाना (पंजाब)	1971
10	केन्द्रीय राज्य फार्म, मिजोरम	1972
11	केन्द्रीय राज्य फार्म, बहराइच, जिला बहराइच (उत्तर प्रदेश)	1973
12	ऊसर सुधार फार्म, लालगंज, जिला रायबरेली (उत्तर प्रदेश)	1973

विवरण-2

भारतीय राज्य फार्म निगम के फार्मों में 1980–81 के दौरान आय, व्यय तथा लाभ/हानि को दर्शाने वाला विवरण

मुख्यालय के भाग सहित व्यय

(आंकड़े लाख रुपये में)

फार्म का नाम	आय	व्यय	लाभ/हानि (+)	(-)
1. सूरतगढ़ (सरदारगढ़ सहित) .	351.78	304.10	(+) 47.68	
2. जेतसर . . .	130.49	110.10	(+) 20.39	

1	2	3	4	5
3.	हिसार . . .	160.48	107.48 (+)	53.00
4.	रायचूर . . .	44.76	71.67 (−)	26.91
5.	कन्नानौर . . .	67.97	66.51 (+)	1.46
6.	चेंगम . . .	16.89	42.30 (−)	25.41
7.	कोकिलाबाड़ी . . .	17.73	34.60 (−)	16.87
8.	लाढ़ोवाल . . .	45.52	60.82 (−)	15.30
9.	बहराइच . . .	32.17	63.80 (−)	31.63
10.	रायबरेली . . .	4.57	6.06 (−)	1.49

मिजोरम स्थित फार्म विस्तार सम्बन्धी कार्यकलाप करता है, अतः यह भारतीय राज्य फार्म निगम के तुलन पत्र में शामिल नहीं किया जाता है ।

Central Scheme for Raising Economic status of Fishermen

4436. SHRI K. PRADHANI :
SHRI G. NARSIMHA REDDY :

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether any centrally sponsored scheme is under implementation or proposed to be implemented to raise the economic status of the fishermen ;

(b) whether his Ministry has advised various State Governments for the spreading of co-operative movement among the fishermen to achieve better financial benefit out of their day to day trade ;

(c) if so, the names of the States where co-operative societies have been formed among the fishermen ;

(d) the steps taken by Government for the formation of co-operative societies by the fishermen in other States ; and

(e) the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (SHRI R. V. SWAMINATHAN) : (a) Under the Centrally sponsored scheme of Fish Farmer's Development Agency, 102 agencies have been set up for the benefit of weaker sections of fishermen. Landing and berthing facilities for fishing crafts at minor ports are also provided under a centrally sponsored scheme. A scheme for the development of brackish water fish farming in maritime states is also proposed to be implemented. Central schemes, viz. National Fish seed Programme, Fish Processing and marketing surveys and construction of major harbours would also benefit the fishermen. An FAO Regional Project viz. 'Bay of Bengal Programme for the development of small scale fisheries' is also in operation with the objectives of improving the conditions of small scale fishermen.

(b) It is the Government's policy to promote cooperatives amongst the fishermen. State Governments are given assistance through the National Cooperative Development Corporation for the development of fishery cooperatives.

(c) to (e). In all the States, Primary Fishery co-operatives societies/